दैनिक भारत कि

# तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

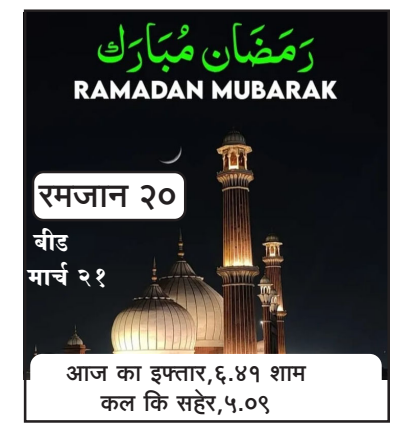


बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२२७ वा | शुक्रवार २१ मार्च २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

# राज्य की सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू, शिक्षामंत्री की सदन में घोषणा

मुंबईः संवादाता

राज्य की सरकारी स्कूलों में अब सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि इस शैक्षणिक वर्ष से ही राज्य बोर्ड की स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न को लागू किया जा रहा है। शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ से यह नया पैटर्न लागू होगा। सरकार ने यह फैसला छात्रों की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है। इस संबंध में राज्य के शिक्षामंत्री दादा भुसे ने आज विधानसभा में घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई बैठक में भी उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की थी और सीबीएसई पैटर्न को लागू करने पर विचार चल रहा है, ऐसा संकेत दिया था।

शालेय शिक्षण विभाग की मंजूरी

शालेय शिक्षण विभाग से संबंधित सुकाणू समिति ने राज्य पाठ्यक्रम योजना को मंजूरी दी है। विधान परिषद में इस मुद्दे पर लिखित उत्तर देते हुए शिक्षामंत्री दादा भुसे ने जानकारी दी। भाजपा नेता और विधायक प्रसाद लाड ने यह सवाल उठाया था कि क्या तीसरी से बारहवीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई है? इसके जवाब में मंत्री दादा भुसे ने बताया कि सीबीएसई के तहत मराठी में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी और १ अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रालय के सभी विभागों की आगामी १०० दिनों की कार्य योजना की समीक्षा की थी। इस बैठक में उन्होंने शालेय शिक्षण विभाग को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र को फिर से शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाए। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य के स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न अपनाया जाए, लेकिन राज्य के अनुसार जरूरी बदलाव किए जाएं। सरकार के इस फैसले से राज्य के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में फायदा मिलने की उम्मीद है।

## पानी आपूर्ति और विकास कार्यों को लेकर विधायक क्षीरसागर विधानसभा में आक्रामक

मुंबई, २० (प्रतिनिधि) - बीड़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को बजट सत्र में उठाते हुए विधायक संदीप क्षीरसागर ने गुरुवार (२० तारीख) को सदन का ध्यान आकर्षित किया। कोविड काल में विकास कार्यों के लिए आवंटित निधि को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने से रुके हुए कार्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की मरम्मत, विभिन्न सुविधाओं की उपलब्धता, सड़कों और पुलों की मरम्मत जैसे अहम मुद्दों पर उन्होंने जोरदार चर्चा की।

बीड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित श्री क्षेत्र कपिलधार देवस्थान महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आस्था स्थल है। यहां महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कोविड महामारी से पहले इस देवस्थान के विकास के लिए १०० करोड़ रुपये का विकास आराखड़ा मंजूर किया गया था, लेकिन महामारी के चलते इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। ऐसे में सरकार को इस धार्मिक स्थल के विकास के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करानी चाहिए।

इसके अलावा, बीड़ विधानसभा क्षेत्र में कुल ३५० स्कूल हैं, जिनमें से ५९२ कक्षाओं की हालत बेहद खराब है और वे गिरने की कगार पर हैं। साथ ही ६३ वस्ती शालाओं की इमारतों के लिए भी निधि की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें और पुल जर्जर हालत में हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (चरण ३) के तहत मंजूरी दी जानी चाहिए। कई ग्राम पंचायत कार्यालयों के लिए भी नई इमारतों की मांग लगातार उठ रही है, जिसके लिए सरकार को तुरंत निधि प्रदान करनी चाहिए। इन महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हुए विधायक संदीप क्षीरसागर ने सदन का ध्यान आकर्षित किया और सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

## अल्पवयस्क लड़की का पता न चलने पर मां ने किया आत्मदहन का प्रयास

### युसूफवडगांव पुलिस थाने में सनसनीखेज घटना

केज, २० (प्रतिनिधि) - डेढ़ महीने से लापता अल्पवयस्क लड़की का कोई सुराग न मिलने पर उसकी मां ने पुलिस थाने में ही आत्मदहन करने का प्रयास किया, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि, समय रहते पुलिस के हस्तक्षेप से बड़ा हादसा टल गया।

करीब डेढ़ महीने पहले एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने की घटना सामने आई थी। इस मामले में युसूफवडगांव पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब तक लड़की का कोई पता नहीं चला है। परिजनों का आरोप है कि जब भी वे पुलिस से मामले की जानकारी मांगते हैं, तो उन्हें टालमटोल भरे जवाब दिए जाते हैं और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी से आहत होकर पीड़ित लड़की की मां आज (२० तारीख, गुरुवार) दोपहर को युसूफवडगांव पुलिस थाने के सामने पहुंची और खुद पर डीजल डालकर आत्मदहन करने का प्रयास किया। महिला पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, अब तक लड़की का कोई सुराग नहीं मिलने के कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

## तेज आवाज, फैंसी नंबर और नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई-पांडकर

बीड़, २० (प्रतिनिधि) - जिले में बेखौफ वाहनचालकों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस ने कमर कस ली है। तेज आवाज वाले सायलेंसर, फैंसी नंबर प्लेट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनचालकों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक सचिन पांडकर ने सख्त चेतावनी दी है।

पिछले कुछ दिनों से बीड़ शहर सहित ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहन चालक अपनी गाड़ियों में तेज आवाज वाले सायलेंसर लगा रहे हैं, खासतौर पर बुलेट बाइक में ऐसे सायलेंसर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इन सायलेंसरों की वजह से आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

यातायात पुलिस ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक १०० सायलेंसर जब्त किए जा चुके हैं। अपर पुलिस अधीक्षक सचिन पांडकर ने वाहनचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपनी गाड़ियों में तेज आवाज वाले सायलेंसर न लगाएं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

## सतीश भोसले की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

बीड़, २० मार्च (प्रतिनिधि) - सतीश भोसले उर्फ खोक्या को शिरूर दीवानी और फौजदारी न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे १४ दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया। शिरूर में ढाकणे पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में सतीश भोसले पहले से ही पुलिस हिरासत में था। सात दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद गुरुवार (२० मार्च) को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

कुछ दिन पहले ही वन विभाग ने खोक्या के घर पर बुलडोजर चला दिया था। वन विभाग की जिस जमीन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा था, वहां बनी आलीशान इमारत और उसके कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि अपराध जगत से जुड़े खोक्या भाई पिछले पांच वर्षों से राजनीति में सक्रिय था। उसकी पहचान भाजपा पदाधिकारी और भाजपा विधायक सुरेश धस के कट्टर कार्यकर्ता के रूप में होती थी।

भाजपा पदाधिकारी और विधायक सुरेश धस के कार्यकर्ता सतीश भोसले उर्फ खोक्या भाई ने शिरूर गांव के दिलीप ढाकणे और उनके बेटे महेश ढाकणे पर हमला किया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। इससे पहले बुलढाणा जिले में एक व्यक्ति को क्रिकेट बैट से पीटते हुए खोक्या का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिससे उसकी दहशत उजागर हुई थी।

इस मामले में पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर केस दर्ज किया था। वहीं, शिरूर में ढाकणे पिता-पुत्र पर हमले के मामले में भी सतीश भोसले के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज किया गया। सात दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

## राज्य में बढ़ते जातीयद्वेष के खिलाफ अंबाजोगाई में प्रदर्शन

अंबाजोगाई, २० (प्रतिनिधि) - महाराष्ट्र और बीड़ जिले में पिछले कुछ दिनों से जातीय द्वेष की घटनाओं में वृद्धि हुई है। आष्टी में जातीय विद्वेष के कारण आकाश बनसोडे की नृशंस हत्या कर दी गई, वहीं सरकार में शामिल एक मंत्री द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया गया, जिससे नागपुर में दंगा भड़का। ऐसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में अंबाजोगाई में उपविभागीय कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन के दौरान सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि महाराष्ट्र में धार्मिक विवाद भड़काने के लिए सरकार के मंत्री भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे समाज में अस्थिरता बढ़ रही है। इसका नतीजा नागपुर में हुई हिंसा के रूप में सामने आया। साथ ही, राज्य सरकार ब्रिटिश काल की तर्ज पर जनसुरक्षा कानून लागू करने की योजना बना रही है, जिससे आंदोलनों और जन आंदोलनों को दबाने की साजिश की जा रही है। इस कानून को तत्काल रद्द किया जाए, ऐसी मांग ज्ञापन में की गई।

इस दौरान भाषण देते हुए कॉमरेड पोटभरे ने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर उन्माद फैलाकर राज्य सरकार जनता को गुमराह कर रही है और दूसरी तरफ आर्थिक शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि जातीय और धार्मिक नफरत के कारण इंसानियत खतरे में पड़ गई है। सरकार को तुरंत ऐसी नीतियों को बंद कर जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो प्रदर्शन और आंदोलन तेज किए जाएंगे, इसकी सरकार को गंभीरता से नोटिस लेनी चाहिए।

## पंजाब के शंभू बॉर्डर से हटाए गए किसान, कार्रवाई पर 'आप'का आया बड़ा बयान

नवी दिल्लीः संवादाता

आम आदमी पार्टी ने पंजाब के शंभू बॉर्डर को प्रदर्शनकारी किसानों से खाली कराए जाने पर स्थिति साफ कर दी है. आप ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए शंभू बॉर्डर को खोलना भी जरूरी है लेकिन पार्टी किसानों की मांगों के साथ हमेशा खड़ी है. सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि किसानों का साथ सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने दिया. उन्होंने कहा, किसानों के खिलाफ लाए गए तीन कृषि कानूनों का विरोध किया. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया. किसानों की आवाज उठाने पर संसद से मुझे निलंबित कर दिया गया.

आप सांसद ने केंद्र सरकार से किसानों को एमएसपी की गारंटी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि एमएसपी के लिए लंबे समय तक पंजाब का रास्ता रोककर रखा जानाउचित नहीं है. संजय सिंह ने कहा, स्थिति को बिगाड़ने के लिए सिर्फ केंद्र की सरकार जिम्मेदार है. केंद्र सरकार एमएसपी गारंटी कानून पर एक घंटे के अंदर फैसला ले सकती है. उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों का रास्ता बंद करना कहां तक उचित है.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है. तीन काले कानून के खिलाफ संघर्ष में भी आप ने किसानों का साथ दिया. उन्होंने कहा, पिछले एक साल से किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए थे. बॉर्डर बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था और व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था. पंजाब सरकार ने ड्रग्स और नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है. युद्ध को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, व्यापार, नौकरी बढ़े. हाईवे पंजाब के लिए लाइफलाइन है. इसलिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार से किसानों की मांगों का आप समर्थन करती है.

राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि किसानों की समस्याओं का निवारण केंद्र सरकार ही कर सकती है. किसान केंद्र सरकार से मांग करें. पंजाब में रास्ता ब्लॉक करने किसानों को भी नुकसान है. उन्होंने कहा, पंजाब सरकार किसानों की हितैषी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान बातचीत के लिए २४ घंटे तैयार हैं. किसानों को मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए. संदीप पाठक ने किसान नेताओं को हिरासत में लेने के मुद्दे पर कहा कि पुलिस स्टैंडर्ड प्रक्रिया का पालन कर रही है. धरनास्थल पर बैठे ज्यादातर किसान खुद ही उठकर चले गए. आप सांसद ने किसानों को उचित तरीके से मांग उठाने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए.

## उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

# दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण पर विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा!

## सत्ताधारी और विपक्ष आमने-सामने

रिपोर्टर: जमीर काज़ी, मुंबई

दिशा सालियन मृत्यु प्रकरण में उनके पिता द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका का असर बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिला। सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (डखढ) की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की और उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला। वहीं, ठाकरे गुट के विधायकों ने सरकार पर जानबूझकर रिपोर्ट दबाने का आरोप लगाया और कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस मुद्दे पर दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।

विधान परिषद में तीखी बहस

विधान परिषद में मंत्री गिरीश महाजन और विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद ठाकरे गुट के नेता अनिल परब और भाजपा विधायक चित्रा वाघ के बीच भी तीखी नोकझोंक हुई। परब ने शिवसेना (शिंदे गुट) की विधायक मनीषा कायंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गिरगिट की तरह रंग बदलती हैं, जिसे देखकर खुद गिरगिट भी शर्मिंदा हो जाए।

परब ने आगे कहा कि जब संजय राठौड़, जयकुमार गोरे और किरीट सोमैया पर गंभीर आरोप लगे थे, तब चित्रा वाघ चुप क्यों थीं? राठौड़ को फिर से मंत्री पद कैसे मिला? इस पर वाघ भड़क गईं और जवाब दिया कि राठौड़ को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने क्लीन चिट दी थी। अगर हिम्मत है तो उनसे जाकर सवाल पूछिए। उन्होंने परब पर पलटवार करते हुए कहा कि आप जैसे ५६ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं।

आदित्य ठाकरे पर फिर लगे आरोप

गौरतलब है कि २०२० में दिशा सालियन की मृत्यु हुई थी। भाजपा नेता नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे ने तब दावा किया था कि इस मामले में आदित्य ठाकरे का हाथ है। हालांकि, दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन ने इसे दुर्घटना करार दिया था और राजनीति न करने की अपील की थी। जून २०२२ में डखढ गठित की गई थी, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। सीबीआई ने भी आदित्य ठाकरे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की बात कही थी।

हालांकि, अब दिशा सालियन के पिता ने उच्च न्यायालय में नई याचिका दाखिल कर कहा है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर हत्या कर दी गई। उन्होंने इस मामले में आदित्य ठाकरे, अभिनेता सूरज पांचोली, दिनेश मोरया और पूर्व महापौर किशोरी पेडणेकर पर संदेह जताया है और जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है। इस मुद्दे ने विधानसभा में भी जोर पकड़ा।

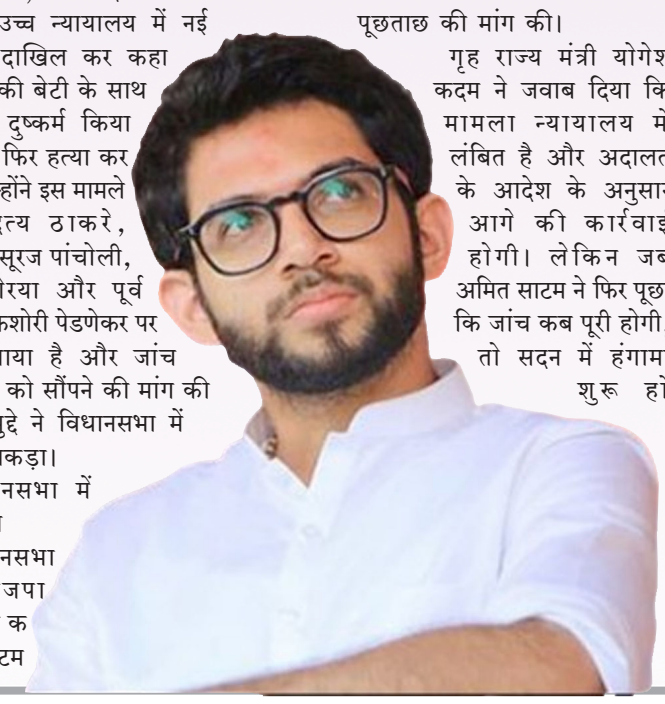

विधानसभा में भी हंगामा

विधानसभा में भाजपा विधायक अमित साटम ने सवाल उठाया कि दिशा सालियन मामले की जांच के लिए डखढ बने १.५ साल हो गए, लेकिन रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? इस पर मंत्री निलेश राणे ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और पूछताछ की मांग की।

गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने जवाब दिया कि मामला न्यायालय में लंबित है और अदालत के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जब अमित साटम ने फिर पूछा कि जांच कब पूरी होगी, तो सदन में हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि मुंबई सपनों का शहर है, जहां देशभर से युवा अपने करियर बनाने आते हैं। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो या किसी के पास सत्ता हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि ऐसे मामले दबा दिए जाएं।

भारी हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कार्यवाही १५ मिनट के लिए स्थगित कर दी।

विधान परिषद में भी गरमाया मुद्दा

विधान परिषद में शिवसेना (शिंदे गुट) की मनीषा कायंदे ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसका ठाकरे गुट ने कड़ा विरोध किया। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने इस पर आपत्ति जताई और मंत्री गिरीश महाजन के साथ उनकी तीखी बहस हो गई।

अनिल परब ने मनीषा कायंदे पर हमला करते हुए उनके पुराने ट्वीट पढ़कर सुनाए, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच के बाद आदित्य ठाकरे को निर्दोष बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कायंदे अब अपने पद के लिए रंग बदल रही हैं। इस पर शिक्षक मंत्री दादा भुसे और निरंजन डावखरे ने कड़ी आपत्ति जताई।

हंगामे के कारण विधान परिषद के उपसभापति निरंजन डावखरे ने १० मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद चित्रा वाघ ने फिर से परब पर निशाना साधा और कहा, राठौड़ को उद्धव ठाकरे ने क्लीन चिट दी थी। अगर हिम्मत है तो उनसे पूछिए।

पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान

इस पूरे विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, आदित्य ठाकरे पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वे खुद फंस जाएंगे। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, उनके पास सभी जांच एजेंसियां हैं, लेकिन वे अब तक इस मामले में कोई निष्कर्ष क्यों नहीं निकाल पाए?

आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया

आदित्य ठाकरे ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पिछले पांच साल से मेरा नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। लेकिन इन आरोपों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अगर अदालत मुझसे कुछ पूछेगी, तो मैं वहां सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा।

# निजी अस्पतालों के लिए शुल्क नियामक समिति गठित की जाए-मुळूक, गलधर

## जिले में मरीजों की आर्थिक लूट रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

बीड़, २० (प्रतिनिधि) - गरीब, वंचित और आम मरीजों के लिए सरकार ने कई स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। लेकिन बीड़ जिले में इन योजनाओं के लागू होने के बावजूद निजी अस्पतालों में मरीजों को इनका लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें भारी भरकम बिल चुकाने के लिए मजबूर किया जाता है। इतना ही नहीं, आईसीयू के नाम पर भी मरीजों से अनाप-शनाप शुल्क वसूला जाता है। इस आर्थिक लूट पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी और जिला सर्जन की अध्यक्षता में शुल्क नियामक समिति का गठन किया जाए, ऐसी मांग शिवसेना जिलाप्रमुख सचिन मुळूक और

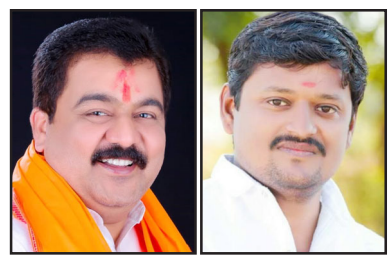

स्वप्नील गलधर ने स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर से ज्ञापन के माध्यम से की है।

बीड़ जिले के निजी अस्पतालों में भर्ती किए जाने वाले मरीजों को स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें इलाज के लिए बड़ी रकम चुकाने पर मजबूर किया जाता है। कई अस्पताल यह कहकर टालमटोल करते हैं कि योजना लागू नहीं है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब मरीजों के साथ अन्याय हो रहा है।

निजी अस्पताल मरीजों से भारी-भरकम बिल वसूलते हैं, लेकिन इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए जिले में एक शुल्क नियामक समिति बनाई जाए, जो जिलाधिकारी और जिला सर्जन की अध्यक्षता में कार्य करे और निजी अस्पतालों द्वारा लिए जा रहे शुल्क की नियमित जांच करे। यह समिति जरूरतमंद मरीजों को न्याय दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी।

इसके अलावा, सरकार ने जिन अस्पतालों को स्वास्थ्य योजनाओं के तहत सेवा देने की अनुमति दी है, उनकी सख्त निगरानी की जाए और तुरंत जांच की जाए। साथ ही, जो अस्पताल गलत तरीके से मरीजों से पैसे वसूल रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी मरीज के साथ अन्याय न हो।

शिवसेना जिलाप्रमुख सचिन मुळूक और स्वप्नील गलधर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

# नागपुर के दंगा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने कांग्रेस ने गठित की समिति

## स्थानीय लोगों से चर्चा कर शांति बहाल करने का प्रयास करेगी टीम

रिपोर्टर: जमीर काज़ी, मुंबई

नागपुर में सोमवार रात हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र की शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। इस स्थिति में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ के निर्देशानुसार दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और स्थानीय लोगों से चर्चा कर शांति स्थापित करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की है।

इस समिति में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गोवा के प्रभारी माणिकराव ठाकरे, पूर्व सांसद हुसेन दलवाई, पूर्व मंत्री डॉ. नितीन राऊत, एडवोकेट यशोमती ठाकुर और विधायक साजिद पठान को सदस्य बनाया गया है। वहीं, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रफुल्ल गुडदे-पाटील समन्वयक की भूमिका निभाएंगे।

इस समिति के गठन की जानकारी प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष (संगठन और प्रशासन) एडवोकेट गणेश पाटील ने दी। उन्होंने बताया कि यह समिति दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेगी और शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com